



हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस



@janexpressnews



janexpresslive

www.janexpresslive.com/epaper



janexpresslive

लखनऊ, गुरुवार, 11 सितंबर, 2025

03

टीईटी की अनिवार्यता : केंद्र पर दबाव बनाने के लिए यूपी में शिक्षकों का विरोध शुरू, अक्तूबर में दिल्ली करेंगे कूच

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षक चिंतित और खड़े हुए हैं। अगर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उनके सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश भर से शिक्षकों द्वारा पहले दिन ही 97890 पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा।



इस दौरान प्रदेश भर के शिक्षक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को

टीईटी से छूट देने की मांग करेंगे। सघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा की 55 साल का शिक्षक कैसे परीक्षा

पास कर पायेगा। अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाए या अब खुद पढ़ें। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार के कानून और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से प्रदेश के काफी शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहराया है। केंद्र सरकार व एनसीटीई चाहे तो शिक्षकों को राहत मिल सकती है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो अक्तूबर में देश भर के शिक्षक दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे।दूसरी ओर एक शिक्षक संगठन की ओर से प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर बुधवार को प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन दिया गया। संगठन के

सुशील कुमार पांडेय ने मांग की कि आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों को इससे मुक्त रखा जाए। आरटी ई एक्ट में संशोधन किया जाए। वहीं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोशिएशन 11 से 25 सितम्बर के बीच पीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने हम पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए अभियान चलाएंगे। प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि संगठन शिक्षकों के लिए हर स्तर पर लड़ई लड़ेगा।



अच्छी और कमजोर सीटों के बीच संतुलन...

बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि सीटों का बंटवारा करते समय अच्छी और कमजोर सीटों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साथ ही, अगर नए दल गठबंधन में शामिल होते हैं... ▶ [पढ़ें पृष्ठ 12 पर...](#)

प्रदेश में बदलेगी बिजली व्यवस्था, नया कनेक्शन लेने पर लगेंगे सिर्फ प्रीपेड मीटर, पुराने मीटर भी बदलेंगे

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने पर अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस संबंध में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी विद्युत वितरण निगम के निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश में पहले से लगे मीटरों को बदला जा रहा है। उन्हें हटा कर नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 37 लाख मीटर लगाए गए हैं। ऐसे में कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी निगमों को निर्देश दिया है कि नए कनेक्शन देते वक स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाया जाए। ताकि भविष्य में उसे बदलने की जरूरत न



अथवा भार वृद्धि पर मीटर बदलने के दौरान प्री-पेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। जहां अभी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है वहां पर जब यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा तो वहां भी स्वतः ही यही व्यवस्था लागू होती रहेगी।

मीटर बदलते समय बरते सावधानी

प्रबंध निदेशक ने यह भी निर्देश दिया गया है कि मीटर बदलते समय विशेष सावधानी बरते। जिन उपभोक्ताओं के यहां मीटर खराब है, जिन्हें हुए हैं, टर्मिनल प्लेट जली है, नो डिस्ले या अन्य प्रकार की खराबी है, वहां स्मार्ट मीटर लगाते समय सभी औपचारिकता पूरी की जाए।

महोना नगर पंचायत में तैनात कर्मचारी को मारा-पीटा



जन एक्सप्रेस | लखनऊ

लखनऊ कमिश्नरेट उत्तरी जोन इटौंजा थाना क्षेत्र के महोना नगर पंचायत में तैनात क्लर्क द्वारा

कर दिया।जिसके चलते कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लिपिक ने इस सम्बन्ध में थाने में लिखित तहरीर दी है। इटौंजा क्षेत्र के महोना नगर पंचायत कार्यालय में तैनात क्लर्क हरीश कुमार पुत्र गेन्दन लाल निवासी मोहल्ल मालीपुरा नगर पंचायत मौरागंज जिला बरेली जोकि महोना स्थित प्रथम पेयजल योजना (टकी) में स्थित भवन में निवास करता है। जहां बुधवार सुबह टंकी पर सफाई करने के लिए सफाईकर्म

ी सफाईकर्मियों से सफाई करने के लिए कहना भारी पड़ गया। बुधवार को सुबह हुई इस घटना में सफाईकर्मियों ने एकजुट होकर क्लर्क पर फावड़ा और लोहे की राड से जानलेवा हमला

संख्या 2 कटरा मोहल्ल नगर पंचायत महोना से टंकी के आसपास घास और गंदगी सफाई करने के लिए कहा तभी तीनों सफाईकर्म एकजुट होकर फावड़ा और लोहे की राड से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे क्लर्क हरीश के सर पर गंभीर चोट लग गई। तभी वहां मौजूद नगर पंचायत कर्म शकील बेग व मिलन रावत बीच-बचाव कर छुड़ाया, तथा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं तहरीर में क्लर्क ने लिखा है कि अंगद गिरि, उमेश और सुनील आपराधिक पृवृत्ति के हैं। वहीं सभी आरोपियों ने बाबू को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

शक्ति केन्द्र मंडल और बूथ के बीच की कड़ी : धर्मपाल

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि सशक्त शक्ति केन्द्र ही मंडल और बूथ के बीच की मजबूत कड़ी है। शक्ति केन्द्र की मजबूत संरचना से बूथ की संरचना मजबूत होगी और मजबूत बूथ से भाजपा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर जवाबदेही का कल्चर तैयार करना है।श्री सिंह ने जौनपुर व मछलीशहर में मंडल अध्यक्ष तथा शक्ति केन्द्र संयोजकों की बैठक के साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारियों की बैठक को सम्बोधित किया और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, सेवा

पखवाड़ा तथा बूथ विजय की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल है और अनुशासित व समर्पित कार्यकर्ताओं का समृद्ध संगठन है। संगठन विस्तार की सतत प्रक्रिया के तहत नए लोगों को संगठन से जोड़ना तथा युवाओं व महिलाओं को कार्यक्रमों व अभियानों में भागीदारी देकर उन्हें सक्रिय करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर चलते हुए सभी वर्गों के साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक व सामाजिक विकास तथा राजनैतिक भागीदारी के लिए सतत कार्य कर रही है।

छात्रों को बांटे गए निशुल्क चश्मा

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

मलिहाबाद। स्कूली बच्चों के बीच दृष्टि दोष जांच के पश्चात चश्मा वितरण कार्यक्रम जहां लोकप्रिय हो रहा है। बुधवार दोपहर को मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक विद्यालय मुजासा, बाकी नगर, कसमंडी कला के बच्चों को मुफ्त चश्मा वितरित किया गया सीएचसी पर आंखों की मुफ्त जांच की जा रही है। डॉ. राकेश कुमार दिवाकर ने बताया कि अभी तक मुस्कान, अलशिफा बानो, नाजिया बानो, तहसीन नूरान सहित आदि बच्चों को चश्मा वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों में तो इस कार्यक्रम के प्रति काफी

जागरूकता आई है लेकिन ग्रामीण बहुत कम संख्या में आंखों की जांच कराने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के बीच इस बात का प्रचार-प्रसार बहुत कम है कि अस्पताल में आंखों की जांच मुफ्त में की जाती है। डॉ. शालिनी वर्मा ने बताया की नेत्रदान एक महान कार्य है जिसके द्वारा दृष्टिहीन व्यक्तियों की नई रोशनी दिला जा सकता है। नेत्र दान करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु उपरांत 6 से 8 घंटे के बीच आंखों को दान कर देना चाहिए। जिसे वह आंख किसी अन्य के काम भी आ सके। नेत्र दान से बढ़कर भी आंखें दान नहीं होता जो दूसरी की जिंदगी को रोशन कर सके। इस मौके पर डॉ. शम्बीर अहमद सहित सीएचसी स्टॉप मौजूद रहा।

इटौंजा मानपुर सब्जी मंडी की दुकानों पर एन.एच.ए.आई की कार्रवाई, दुकानों को किया ध्वस्त, दुकानदारों में नाराज़गी

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

लखनऊ जिले के लखनऊ सीतापुर हाईवे इटौंजा टोल प्लाजा के निकट मानपुर सब्जी मंडी लगने के कारण जाम की समस्या बनी हुई थी,जिससे क्षेत्र के नागरिकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, इसी क्रम में बुधवार सुबह इस ओर कार्रवाई करते हुए एन.एच.ए.आई के अधिकारियों द्वारा सड़क किनारे बनी सब्जी मंडी की दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि, क्षेत्र के नागरिकों तथा रोजे आने-जाने वाले व्यक्तियों को प्रायः सब्जी मंडी की वजह से जाम से होकर गुजरना पड़ता था सब्जी मंडी के कारण ही कई लोग बड़े वाहनों से टक्कर खाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसको देखते हुए बुधवार हम लोगों द्वारा सब्जी मंडी को हटया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि



किसानों के लिए कि किसी अन्य जगहों पर व्यवस्थित सब्जी मंडी बनाई जाए,जिससे कि क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल व सब्जियां आने पौने भावों पर ना बेचनी पड़े और किसान व्यापारियों के शोषण से बच सकें। वहीं क्षेत्र के किसानों का कहना है कि, सरकार द्वारा हमारी रोजी-रोटी छीन ली गई। वहीं एनएचएआई ने शासन से इस अवैध मंडी को हटाने की मांग की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान, बख्शी का तालाब के एसडीएम और एसीपी ने किसानों और दुकानदारों को हाईवे से दूर अपनी दुकानें लगाने के निर्देश दिए। वहीं कार्रवाई के समय, मौके पर भारी पुलिस बल और एनएचएआई की टीम मौजूद थी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निवृत्ता जा सके। हालांकि, इस बुलंदोजर कार्रवाई को लेकर किसान और दुकानदारों में काफी गुस्सा और आक्रोश देखा गया।

महोना नगर पंचायत में तैनात कर्मचारियों को मारा-पीटा, पुलिस से शिकायत

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

लखनऊ कमिश्नरेट उत्तरी जोन इटौंजा थाना क्षेत्र के महोना नगर पंचायत में तैनात क्लर्क द्वारा सफाईकर्मियों से सफाई करने के लिए कहना भारी पड़ गया। बुधवार को सुबह हुई इस घटना में सफाईकर्मियों ने एकजुट होकर क्लर्क पर फावड़ा और लोहे की राड से जानलेवा हमला कर दिया।जिसके चलते कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए अस्पताल ले जाया



गया। लिपिक ने इस सम्बन्ध में थाने में लिखित तहरीर दी है। इटौंजा क्षेत्र के महोना नगर पंचायत कार्यालय में

तैनात क्लर्क हरीश कुमार पुत्र गेन्दन लाल निवासी मोहल्ल मालीपुरा नगर पंचायत मौरागंज जिला बरेली जोकि

हीटवेव से निपटने के लिए मिलकर करना होगा सरकारी, गैरसरकारी संगठनों को काम : डिमरी

■ प्रदेश में सिटी हीट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु हुई कार्यशाला

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभागार में 'सिटी हीट एक्शन प्लान' विषय पर परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी पीबीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेनि. ने की। बैठक का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए हीट एक्शन प्लान की तकनीकी प्रस्तुतियों और प्रस्तावों का आकलन करना था।राजस्व सचिव एवं राहत आयुक्त,अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने कहा कि भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिवर्तन के चलते प्रदेश में हीटवेव की तीव्रता एवं आवृत्ति बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट सतह, यातायात एवं औद्योगिक कारणों से तापमान और अधिक बढ़ जाता है। सिटी हीट एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे धरातल पर लागू कर जनता को सीधा लाभ मिल सके। प्राधिकरण ने लखनऊ, आगरा और वाराणसी शहर के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान विकसित किया है जबकि कानपुर और प्रयागराज के लिए यह तैयार



किया जा रहा है। अन्य शहरों हेतु भी शीघ्र ही योजना बनाई जाएगी। कार्यशाला में डॉ. कनीज फातिमा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने राज्य, जनपद और सिटी भन्च् का अवलोकन प्रस्तुत किया।। महावीर गोलेच्छ, प्रोफेसर एवं प्रमुख गांधीनगर ने स्थानीय निकायों से समन्वय और जनजागरूकता के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी ने कहा कि हीटवेव की चुनौती से निपटने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। नगर निगम के अधिकारियों को तकनीकी सहयोग देने, पूर्वावरण व जनस्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने और हीट से संबंधित बीमारियों की रोकथाम हेतु योजनाबद्ध कार्यवाही जरूरी है।बैठक का समन्वय प्रवीन किशोर, प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर ट्रेनिंग एवं प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट एग्रीकल्चर ने किया।

कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान दे रहा कैंसर मरीजों को उच्चतम स्तर का उपचार

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान अपने विश्वस्तरीय मशीनों, योग्य चिकित्सकों व उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ कैंसर रोगियों के उपचार में उच्च मानक स्थापित कर रहा है। संस्थान की लोकप्रियता बढ़ने से यहां सुरूर स्थानों से आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान के निदेशक प्रो. मदन लाल ब्रह्म भट्ट ने बताया कि कैंसर संस्थान में सप्ताह में छः दिन ओपीडी सेवा

■ शिक्षा, शोध एवं उपचार में गुणात्मक वृद्धि से बढ़ रही है संस्थान की लोकप्रियता

■ उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत सहयोग मिल रहा है: भट्ट

संचालित है,400 मरीज ओपीडी से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे सभी संकाय विभाग सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं। संस्थान में 280 इन्डोर कूड संचालित है, जिसे शीघ्र ही 500 कर लिया जायेगा, कैंसर संस्थान में आठ अपरेशन थियेटर के



माध्यम से प्रति सप्ताह औसत 12 से 15 सर्जरी की जा रही है। संस्थान के कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है। वृहत स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व कार्मिकों की नियुक्ति की गयी है तथा उच्च वैश्विक तकनीक पर आधारित अत्याधुनिक

मशीनों की खरीद की गयी है। जिन प्रमुख मशीनों की खरीद की गयी है उनमें साइबर नाइफ, पेट सीटी, उच्चस्तरीय ब्रेकीथेरेपी डिजिटल रेडियोग्राफी, युएसजी मशीन के साथ लगभग 5.5 करोड़ की लागत से, डीजीटल मेमोग्राफी युरिंट का संचालन प्रमुख है। टेमोथेरेपी, डिजिटल पैथालॉजी, न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप की खरीद की जायेगी। संस्थान में विश्वस्तरीय बल्ट बैंक भी स्थापित किया गया है। संस्थान में चिकित्सा शिक्षा हेतु चार नये विभागों के संचालन के लिए मान्यता ली गयी है तथा शोध

व नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईआईटी जैसे संस्थानों से 11 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं। निदेशक ने बताया कि संस्थान में प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, आयुष्मान भारत योजना, आसथाय्य रोग योजना तथा दीनदयाल केशलेस योजना से हजारों की संख्या में रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं के संचालन में सरकार का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। संस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन पर्यावरण व रोगी कल्याण की दिशा में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है।

नेपाल सीमा पर अटके 500 से ज्यादा ट्रक, यूपी से 200 करोड़ का निर्यात टप



जन एक्सप्रेस | लखनऊ

उत्तर प्रदेश से नेपाल को होने वाले निर्यात और कारोबार पर संकट गहराता जा रहा है। नेपाल सीमा पर हालाता बिगड़ने के चलते हजारों करोड़ रुपये का निर्यात प्रभावित हो गया है। स्थिति यह है कि सिर्फ 24 घंटे में करीब 200 करोड़ रुपये का माल यूपी की सीमा पर अटका पड़ा है और नेपाल जाने वाले कम से कम 500 ट्रक सीमाओं पर फंसे हुए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि हालात फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे हैं और निर्यातकों की नजरें अगले तत्कालक्रम पर टिकी हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल को भेजा गया माल न सिर्फ अटका है बल्कि उसके भुगतान पर भी संकट मंडा रहा है।

12 हजार करोड़ का निर्यात, 28 प्रतिशत यूपी की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश से हर साल करीब

12,000 करोड़ रुपये का निर्यात नेपाल सहित अन्य देशों को होता है। भारत कुल निर्यात में 63 फीसदी हिस्सेदारी रखता है जबकि नेपाल के व्यापार में चीन की हिस्सेदारी 14 फीसदी है। इसमें अकेले यूपी का हिस्सा लगभग 28 फीसदी है।

ये वस्तुएं होती हैं निर्यात

राज्य से नेपाल और अन्य देशों को मशीनरी उपकरण, कंक्रीट मिक्सचर मशीन, आयरन-स्टील, एल्युमिनियम, केमिकल्स, टॉयलेटरजी, कॉस्मेटिक्स, पीवीसी पाइप, सोडा एश, खाद्य तेल, अनाज-सब्जियां, चावल-दाल, ऑटो पार्ट्स, ई-रिक्षा व बैटरी रिक्षा के पार्ट्स, लेदर उत्पाद, टेक्सटाइल्स, मैग्नेट फाइबर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलईडी, मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर जाते हैं।

दो से तीन दिन की देरी

निर्यातकों ने बताया कि सामान्य स्थिति में नेपाल तक माल पहुंचाने में

भुगतान फंसने का खतरा

निर्यातकों ने चिंता जताई है कि जिनका माल उधारी पर गया है, उनका पैसा फंस सकता है। वहीं, जिन्होंने एडवांस भुगतान लिया है, वे इस समय अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में हैं। व्यापार जगत के जानकारों का मानना है कि अगर यही हालात और दिनों तक बने रहे तो यूपी के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। निर्यातकों को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है और छोटे निर्यातकों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होगी। फेडरेशन के आलोक श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि हालात फिलहाल सामान्य नहीं हैं। निर्यातकों ने भी ट्रकों को तीन दिन में वापस बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कारोबारी समुदाय अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि सीमा पर अटकी अड़चन जल्द दूर होगी और व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ेगा।

दो से तीन दिन लगते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में गाड़ियां सीमा पर खड़ी रह गई हैं। जिन वाहनों को माल सीमा पार करना था, उन्हें रोक लिया गया है। निर्यातक एस.के. आहूजा ने कहा कि मशीनों की सप्लाई हो चुकी है। हमें भुगतान एक हफ्ते में मिलना था, लेकिन हालात देखकर कहना मुश्किल है कि पैसा कब मिलेगा। वहीं, लेदर उत्पादों का निर्यात करने वाले असद अहमद ने बताया कि उनके कूड वाहन नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कुछ ट्रक सीमा पर ही अटके हुए हैं।





जन एक्सप्रेस



सम्पादकीय

सोशल मीडिया को शांत करने से नेपाल हुआ अशांत

ऐसे में नेपाल में बढ़ती अस्थिरता का सीधे प्रभाव भारत की सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों की स्थिरता और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों पर पड़ सकता है। नेपाल में युवाओं का आक्रोश और विरोध प्रदर्शन यह संकेत देते हैं कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का संकट गहरा रहा है। अगर यह स्थिति और बिगड़ी तो चीन अपना प्रभाव वहां और बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। चीन पहले से ही नेपाल में अपनी पकड़ बनाये हुए है। ऐसे में नेपाल के लोकतांत्रिक संस्थानों में अविश्वास और अशांति बढ़ी तो यह भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है।

नेपाल में सरकार द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध ने देश के राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। यह केवल डिजिटल नीति का सवाल नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवा चेतना के लिए एक गंभीर चुनौती है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म, जिन्हें युवा पीढ़ी अपने विचार व्यक्त करने, दोस्तों से जुड़ने और वैश्विक घटनाओं से अपडेट रहने के लिए इस्तेमाल करती है, उन पर बैन लगाने से युवाओं में गहरी नाराजगी और असंतोष पैदा हुआ है। युवा पीढ़ी पहले ही देश की कमजोर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से तंग आ चुकी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर पाबंदी ने उनकी निराशा को और बढ़ा दिया है। हाल ही में 'नेपो किड्स' यानि राजनीतिक परिवारों के बच्चों के विरुद्ध उभरे गुस्से और काटमांडू में जनरेशन जेड के युवाओं का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वह अब अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। यह चेतावनी है कि यदि सरकार युवा वर्ग की भावनाओं को समझने में विफल रही, तो राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। देखा जाये तो इस घटनाक्रम का भारत और दक्षिण एशिया के लिए एक खतरा पैदा कर सकती है, बल्कि चीन जैसे बाहरी प्रभावों को बढ़ावा देने का अवसर भी दे सकती है। हाल ही में 'ओली सरकार का चीन के प्रति झुकाव, पश्चिम और जापान से दूरी और सीमा विवादों में आक्रामक रुख ने यह संकेत दिया है कि नेपाल अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद विदेशी प्रभावों के जाल में फंस्ता जा रहा है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया को कानूनी और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नियंत्रित करना आवश्यक था, लेकिन इसे कैबिनेट निर्णय के माध्यम से लागू करना और विवादास्पद प्रावधान लागू करना— जैसे 'समस्याग्रस्त सामग्री' को 24 घंटे में हटाना, जैसी नीति को थोपना गलत था। पहले ही दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। श्रीलंका, पाकिस्तान और अब नेपाल के हालात यह संदेश देते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रह सकता; इसे जीवित बनाए रखने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता, उनके अधिकार, शासन में पारदर्शिता और संवेदनशील कूटनीति की रक्षा आवश्यक है। नेपाल की सरकार को अब यह समझना होगा कि विदेशी ऐप्स को कानूनी दायरे में लाना उचित है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने युवाओं और नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करें। युवा पीढ़ी देश के भविष्य के निर्माता हैं; उनकी आवाज़ को दबाना, उन्हें अपमानित करना और डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण लगाना केवल अस्थायी समाधान होगा, जबकि अस्थिरता और सामाजिक तनाव स्थायी रूप से बढ़ सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, सोशल मीडिया पर पाबंदी और युवा विरोध प्रदर्शन न केवल वहां की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि यह भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं। नेपाल भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच खुले सीमावर्ती संबंध, सामाजिक-सांस्कृतिक मेलजोल और आर्थिक संबंध गहरे हैं।

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

हल्दी और सरसों के तेल से ऑयल पुलिंग करने के फायदे

भारतीय घरों में हल्दी और सरसों के तेल दोनों का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है। इनमें अच्छी मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं। इनका सेवन करने से स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इनको ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इनसे मुंह के स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से राहत देने में मदद मिल सकती है। डॉ. अनंत त्रिपाठी के अनुसार, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में से एक हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी- माइक्रोबियल के गुण और बहुत से पोषक तत्व होते हैं। वहीं, सरसों के तेल में एंटी-फंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं। इनका ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है।

मसूखें और दांतों को मजबूती: हल्दी और सरसों के तेल में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल के गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल करने से मसूखें और दांतों को मजबूती देने, सड़न से बचाव करने और इनसे जुड़ी अन्य समस्याओं से राहत देने में मदद मिलती है।

हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करें: औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी और सरसों के तेल में अच्छी मात्रा में



एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-माइक्रोबियल के गुण होते हैं। ऐसे में हल्दी और सरसों के तेल से दांतों और मसूखें के दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है, साथ ही, इससे ओरल हेल्थ स्वस्थ रहती है।

कैविटी से बचाव करें: सरसों के तेल और हल्दी में अच्छी मात्रा में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं। इससे ऑयल

पुलिंग करने से दांतों के दर्द को कम करने और दांतों का कैविटीज से बचाव करने में मदद मिलती है।

मुंह की बदबू दूर करें: ऑयल पुलिंग के लिए हल्दी और सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू से राहत देने और मुंह में बैक्टीरिया को पनपने से रोकने में मदद मिलती है, जो ओरल हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं।

निष्कर्ष: हल्दी और सरसों के तेल से ऑयल पुलिंग करने से दांतों और मसूखें को मजबूती देने, दर्द और सूजन को कम करने, मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने, कैविटीज से बचाव करने और मुंह की बदबू को दूर करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इसको निगलना नहीं है।

विचार एक्सप्रेस



पीएम मोदी ने इटली की पीएम जोर्जिया मेलोनी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी इतालवी समकक्ष जोर्जिया मेलोनी के साथ भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की और इसके समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। फोन पर बातचीत में, मोदी ने मेलोनी ...

आज का पंचांग

किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय, और सही नक्षत्र का होना जरूरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज का कौन सी दशा कौन से टाइन में चल रही है-उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे हैं, आज आपका दिन मंगलकरी रहे, यही शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के पौर्णिमा के अनुसार जानें। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे हैं, प्रोपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आपका कार्य शुभ और सफल होगा, वही हमारी और से शुभ मंगल कामना है।

तिथि:	चतुर्थी 12:26 तक
नक्षत्र:	अश्लेषा 13:58 तक
पक्ष:	कृष्ण
वार:	गुरुवार
योग:	धूप, 17:01 तक
सूर्योदय:	06:04
सूर्यास्त:	18:23
चंद्रमा:	मेघ राशि में
राहुकाल:	13:46-15:18
विक्रमी संवत्:	2082
शक संवत्:	1947
मास:	भाद्रपद
शुभ मुहूर्त:	11:49 -12:38

जन एक्सप्रेस

लगा उन्हें है रोग !

बार बार दुहराकर टप ।

बन रहे महान ॥

भारत उनकी बात का ।

ना लिया संज्ञान ॥

बन कर अब बड़बोले वो ।

है रहे उमर ॥

लेकिन ना आसान है ।

उनकी ये उमर ॥

असली मुद्दे से वो ।

रहे अब भटक ॥

आगे इस पर है अडिग ।

है इसमे भी शक ॥

बोलने का ज्यादा १??

लगा उन्हें है रोग ॥

होगे जल्द असहज ।

अमरीका के लोग ॥



- कृष्णेंद्र राय

एक्सप्रेस आलेख

बीजेपी का मानना है कि कि यह विधेयक सुशासन की सबसे बड़ी बाधाओं-भ्रष्टाचार और अपराध को दूर करने के लिए संसद में पेश किया गया है। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के सामने सबको बराबर का दर्जा हासिल है। फिर भी हकीकत यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी दो दिन भी जेल में रहा, तो उसे सेवा नियमों के तहत स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है। जबकि महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों पर यह प्रावधान नहीं लागू होते। बीजेपी का तर्क है कि प्रस्तावित कानून के दायरे में मंत्री,मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री भी आएंगे।

भ्रष्टाचार रोकने वाला कानून हो पाएगा पास?



उमेश वरुवर्दी

बीजेपी का कहना है कि सामाजिक न्याय और समानता का पाठ पढ़ाने वाले दलों के लोग चाहते हैं कि उच्च पदों पर बैठे मंत्री या मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे से सरकार चलाएँ। बीजेपी का तंज है कि यह समानता और सामाजिक न्याय का उपहास है। ऐसे ध्यान रखना होगा कि लिली थॉमस मामले के बाद नियम बनाया गया कि अगर किसी सांसद को दो साल से ज्यादा की सज़ा होती है।

संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 संसद के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त दिन बुधवार को लोकसभा में जब पेश किया गया, तब सदन में अभूतपूर्व हंगामा दिखा। कह सकते हैं कि अराजक दृश्यों के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। अब इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति सुझाव मांगेगी और अपने संशोधनों के साथ सदन में भेजेगी। तब कहीं जाकर चर्चा होगी और विधेयक पास हो पाएगा। लेकिन जिस तरह विपक्ष इस विधेयक की राह में अड़ो खल रहा है, उससे लगता नहीं कि संयुक्त समिति में भी इसे आसानी से वह आम राय बनाने देगा और भ्रष्टाचार के खाले की दिशा में मील का पत्थर माना जाने वाला यह विधेयक पास हो पाएगा।

अव्वल तो होना यह चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोकने, सर्वोच्च स्तर तक के लोगों को जवाबदेह बनाने वाले विधेयक पर पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी साथ होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा मचाए हुए है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं। जिन पाठकों को संसद की संयुक्त समिति की जानकारी नहीं है, उनके लिए यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि यह समिति आखिर है क्या और इसका क्या अधिकार है? इस संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि जो भी मंत्री, किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहेगा, वह अपना पद खो देगा। इस कानून के तहत 0कोई मंत्री, पद पर रहते हुए लगातार तीस दिनों की अवधि के दौरान, किसी ऐसे कानून के तहत किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, जिसके तहत पांच वर्ष या उससे अधिक जेल हो सकती है, उसे हिरासत में लिए जाने के इकतीसवें दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस विधेयक में कहा गया है कि, -यदि ऐसे मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह इकतीसवें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तो वह उसके बाद खुद-ब-खुद मंत्री नहीं रह पाएगा।- विपक्षी निशाने पर आया यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करेगा, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस विधेयक में मंत्री के जेल से वापस आने के बाद को लेकर स्पष्टता तो नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जब मंत्री जेल से रिहा हो जाएंगे तो क्या होगा? कैसे माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों के तहत, सैद्धांतिक रूप से यह संभव हो सकेगा कि संबंधित मंत्री जेल से बाहर आने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इस विधेयक की उपधारा एक का प्रावधान कहता है कि कोई बात ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने पर राष्ट्रपति द्वारा बाद में मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी।- विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार



भारतीय समाज में भ्रष्टाचार गहरे तक जड़ें जमा चुका है। राजनीति का आज दूसरा अर्थ ही भ्रष्टाचार हो गया है। पड़ोसी चीन जैसे देश में भ्रष्टाचार की सजा मौत तक है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि जिन देशों के लोकतंत्र और संसदीय परंपरा की हम खूब दुहाई देते हैं।

जानबूझकर विपक्षी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। कैसे माना जा रहा है कि शराब नीति घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया, तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसकेपहले तक होता रहा है कि जब किसी मंत्री या मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं तो गिरफ्तारी के पहले ही वे इस्तीफा देते रही हैं। 1997 में चारा घोटाले में जब लगा कि लालू यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह 2024 में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगा कि वे गिरफ्तारी से नहीं बच पाएंगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया गया था। लेकिन केजरीवाल ने तब इस्तीफा दिया,जब उन्हें जेल में रहते किसी फाइल पर हस्ताक्षर करने या जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री के दफ्तर ना जाने की शर्त सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। विपक्ष का तर्क है कि केंद्र सरकार अक्सर बदले की भावना के साथ काम करती है और उसके निर्देशन में काम करने वाला प्रवर्तन निदेशालय. आयकर विभाग और सीबीआई जब चाहे किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद ये एजेंसियां ऐसे आरोप लगा सकती हैं. जिनके तहत उन्हें महीनों तक जमानत नहीं मिल सकती। तब इस विधेयक के जरिए किसी भी विपक्षी सरकार को गिराया जा सकता है। यही वजह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश किया तो सदन में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद केंसी वेणुगोपाल ने 2010

में सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गृह मंत्री की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। हालाँकि, शाह ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जानते हैं कि संसद की संयुक्त समिति क्या है? संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जाँच के लिए गठित की जाती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, संविधान के 130वां संशोधन विधेयक, 2025 को विपक्षी हंगामे और मांग के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 31 सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। कैसे तो समिति से रिपोर्ट हासिल करने की कोई मियाद तय नहीं है,लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने मांग की है कि समिति संसद के अगले यानी शीत सत्र के पहले दिन से पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। संसदीय नियमों के अनुसार, जेपीसी का कार्यक्षेत्र उसके गठन के प्रस्ताव पर निर्भर करता है। हालाँकि इसकी सिफारिशें प्रभावशाली होती हैं, लेकिन वे सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं। इस बीच बीजेपी ने 25 अगस्त, 2025 को विपक्षी हंगामे के खिलाफ कड़ा बयान दिया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया 130 वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीति में नैतिकता और सुशासन को मजबूत करेगा और भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करने के लिए एक प्रभावी हथियार के रूप में काम करेगा। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक ओर समूचा राष्ट्र इस पहल का स्वागत कर रहा है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल केवल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी विपक्ष को बहिष्कार ब्रिगेड बताते हुए यह भी कहने से नहीं हिचकी कि विपक्ष यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लोकतंत्र में नहीं, अपने परिवार और सत्ता की रक्षा में ही दिलचस्पी है।

एक्सप्रेस विशेष

जीवन की रक्षा में संवाद ही सबसे बड़ा हथियार

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से प्रतिवर्ष 10 सितम्बर को दुनियाभर में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से ‘विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस’ मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत ‘इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन’ (आईएसपी) द्वारा 2003 में की गई थी। इन दिन एक पीले रंग के रिबन को प्रतीक के रूप में पहना जाता है, जो इस बात को फैलाने में मदद करने के लिए पहना जाता है कि आत्महत्या की रोकथाम के बारे में बोलने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर शोध करना, जागरूकता फैलाना और डेटा एकत्रित करना है। दरअसल डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया में हर 40 सैंकड़ के एक व्यक्ति आत्महत्या करता है यानी प्रतिवर्ष दुनियाभर में करीब आठ लाख लोग आत्महत्या के जरिये अपनी जीवनलीला खत्म कर डालते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में आत्महत्या के मामले 15 से 29 वर्ष के लोगों में होते हैं जबकि आत्महत्या का प्रयास करने वालों का आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है। आत्महत्या रोकथाम दिवस की 2025 की थीम है ‘आत्महत्या पर

बहरहाल, यदि कभी जरूरत से ज्यादा तनाव अथवा किसी मानसिक बीमारी का अहसास हो तो तुरंत किसी मनोचिकित्सक से मिलकर अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करें। केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त 2020 में एक मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन (किरण हेल्पलाइन) नंबर भी जारी किया गया था, जिस पर कॉल करके ऐसी स्थिति में मदद या काउंसलिंग की मांग की जा सकती है।

कहानी बदलना’। इस थीम का उद्देश्य आत्महत्याओं को रोकने के लिए कलंक को कम करने और खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लोगों में अवसाद निरन्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते ऐसे कुछ व्यक्ति आत्महत्या जैसा हृदयविदारक कदम उठ बैठते हैं। लोगों में जीवन से निराश होकर आत्महत्या की बढ़ती दुष्प्रवृत्ति गंभीर चिंता का सबब बन रही है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में 79 फीसदी आत्महत्या निम्न और मध्यम वाले देशों के लोग करते हैं और इसमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की होती है, जिनके कंधों पर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है। हालाँकि बीते वर्षों में दुनियाभर में खुदकुशी की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा काफी चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2022 में भारत में आत्महत्या के मामलों को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वर्ष 2022 में

लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका उनके परिवार के साथ-साथ समाज पर भी बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अवसाद और तनाव के कारण ही लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है और जब व्यक्ति को परेशानियों से बाहर निकलने का कोई मार्ग नजर आता, ऐसे में वह आत्महत्या जैसा हृदयविदारक कदम उठ बैठता है। हालाँकि जिन लोगों का मनोबल मजबूत होता है, वे प्रायः विकट परिस्थितियों से उबर भी जाते हैं लेकिन अवसाद के शिकार कुछ लोग विषम परिस्थितियों से लड़ने के बजाय हालात के समक्ष घुटने टेक स्वयं को मौत के हवाले कर देते हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार आत्महत्या करना काफी गंभीर समस्या है और आत्महत्या करने के पीछे अधिकांशतः अवसाद को ही जिम्मेदार ठाया जाता है, जो ऐसे करीब 90 फीसदी मामलों का प्रमुख कारण भी है लेकिन सभी आत्महत्याओं के लिए अवसाद को ही पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनके मुताबिक आत्महत्या करना का विचार किसी इंसान के अंदर तब पनपता है, जब वह किसी मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाता। मनुष्य जीवन को संसार में सबसे अनमोल माना गया है क्योंकि हमारा यह जीवन एकमात्र ऐसी चीज है, जिसे हम दोबारा नहीं पा सकते।

विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 : संवाद और सुझाव से जालौन ने दी अपनी भागीदारी

जन एक्सप्रेस । उरई

हमारा विज़न-हमारा भविष्य : समर्थ उत्तर प्रदेश @2047 पर जालौन में मंथन। विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विषय पर विचार विमर्श एवं सुझाव कार्यक्रम में सदर विधायक गोरीशंकर वर्मा, मण्डलायुक्त झांसी/नोडल अधिकारी विमल कुमार दुबे, सेवानिवृत्त आईएएस विजय सिंह निरंजन, सेवानिवृत्त आईपीएस हीरा लाल, प्रो. डॉ. रामकाश (वैज्ञानिक, कृषि विभाग), प्रो. डॉ. आदित्य कुमार (राजनीति विज्ञान विभाग, डीवी कॉलेज), जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गाश कुमार द्वारा आयोजन किया गया। इस दौरान मण्डलायुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश और भारत का भविष्य हमें तय करना है। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत संकल्प का हिस्सा है। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर दिए गए सुझाव 12 प्रमुख सेक्टरों- कृषि, पशुधन, उद्योग, आईटी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य



विकास, आधारभूत संरचना, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सुशासन-के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश @2047 केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का साझा दायित्व है। विकसित परिवार से विकसित समाज और विकसित समाज से ही विकसित राज्य व विकसित भारत का निर्माण संभव है। जिलाधिकारी ने

कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम वर्ष 2047 में कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, इस पर स्पष्ट रोडमैप बने। जालौन में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है। यहाँ पाँच नदियाँ हैं, सौर ऊर्जा से 6 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, कृषि उत्पादकता में जनपद ने राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान पाया है। जालौन को उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का इंजन बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर व्यवसायी, उद्यमी, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया प्रतिनिधि एवं आम जनमानस ने भी अपने मूल्यवान सुझाव साझा किए। इस अवसर पर सीडीओ केके सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनोरंजा रामेंद्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मंडी सचिव बिना मंडी शुल्क जमा किए जा रहे ट्रक को पकड़ा जन एक्सप्रेस/जालौन। बिना मंडी शुल्क जमा किए लाही लाइकर ने जा रहे ट्रक को चेकिंग के दौरान मंडी सचिव ने पकड़ा। ट्रक में 230 क्विंटल लाही लदी हुई पाई गई। जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। पकड़े गए ट्रक को मंडी परिसर में खड़ा कराया गया है और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बिना मंडी शुल्क जमा किए उपज का परिवहन करने की सूचना मिलने पर मंडी सचिव रवि कुमार, सहायक राधेंद्र, योगेश कुमार व टीम के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास चेकिंग कर थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश की ओर से एक ट्रक आता दिखा। जिसको रोककर ट्रक की जांच की गई तो उसमें 230 क्विंटल लाही लदी हुई थी। मंडी सचिव ने मंडी से संबंधित प्रपत्र मांगे तो चालक नहीं दिखा सका। पुष्पों पर ट्रक चालक ने बताया कि वह लाही को बनारस लेकर जा रहा था। कागजात न मिलने पर मंडी सचिव ने ट्रक को माल सहित मंडी परिसर में खड़ा कराया है। मंडी सचिव रवि कुमार ने बताया कि ट्रक में 230 क्विंटल लाही लदी हुई थी। जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये है। मंडी शुल्क संबंधित आवश्यक प्रपत्र चालक नहीं दिखा सका। ट्रक को माल सहित मंडी परिसर में खड़ा कराया गया है और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करती हैं रैगिंग जैसी गतिविधियां

जन एक्सप्रेस । अलीगढ़

इगलास। मंगलायतन विश्वविद्यालय में आयोजित दिशा कार्यक्रम के दूसरे दिन एप्लाइड साइंस कृषि और बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्र आयोजित हुआ। इस सत्र में विद्यार्थियों को केवल एंटी-रैगिंग नीति और अनुशासन से अवगत ही नहीं कराया गया, बल्कि उन्हें नेतृत्व, जिम्मेदारी और सकारात्मक माहौल बनाने की प्रेरणा भी दी गई। सत्र के दौरान बताया गया कि रैगिंग जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। विश्वविद्यालय में ऐसी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कुलसचिव ब्रिगेडियर समखीर सिंह ने कहा कि वरिष्ठ विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आचरण और व्यवहार से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि रैगिंग अपराध है, विद्यार्थी आपसी संवाद, सहयोग और भाईचारे को मजबूत करें, यही स्वस्थ शैक्षणिक संस्कृति की पहचान है।



चीफ प्रॉक्टर प्रो. प्रमोद कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार हर छात्र की प्रगति में सहभागी है। अनुशासन और सहयोग के साथ ही विद्यार्थी अपनी असली क्षमता का विकास कर सकते हैं। वहीं, प्रॉक्टर प्रो. किशन पाल सिंह ने कहा कि यह खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय में कोई रैगिंग से संबंधित मामला संज्ञान में नहीं आया है। सुरक्षा और सहयोग का वातावरण तैयार करना सभी का दायित्व है। कार्यक्रम का संचालन एंजला फातिमा ने किया।

नगर पालिका परिषद महोबा में अमृत 2.0 पेयजल पुनर्गठन योजनान्तर्गत कवरई बांध से अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति कार्य हेतु 200 करोड़ धनराशि स्वीकृति जन एक्सप्रेस/महोबा। सदर विधायक राकेश कुमार गोस्वामी अपनी विधान सभा में विकास को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं और समय समय पर सरकार के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य, सड़क पानी सहित सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी आम जनमानस को भरपूर लाभ दिलाने के लिए कार्य करते हैं। श्री गोस्वामी ने कहा कि हम महोबावासियों को शुद्ध पेयजल एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। उन्होंने बताया कि भरे लगातार अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं नगर विकास मंत्री ए0 के0 शर्मा द्वारा महोबा सदर विधानसभा के नगर पालिका परिषद महोबा में अमृत 2.0 पेयजल पुनर्गठन योजनान्तर्गत कवरई बांध से अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति कार्य हेतु रु. 200 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है जिसकी प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण करके कार्य प्रारंभ होगा और आम जनमानस को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने महोबावासियों की ओर से मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है।

नो हेलमेट, नो फ्यूल के तहत दस दिन में कटे 690 चालान



जन एक्सप्रेस । उरई

सड़क दुर्घटना रोकने के लिए चलाए जा रहे नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान के तहत दस दिनों में लगभग 690 चालान काटे गए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद भी बड़ी संख्या में लोग बिना हेलमेट के पंपों पर पेट्रोल ले रहे हैं। एआरटीओ ने बिना हेलमेट पेट्रोल दे रहे पंप कर्मियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। साथ ही मामले में एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार ने बताया कि शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं

दिए जाने का सख्त निर्देश है। इसके बावजूद लोग बिना हेलमेट पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट के दस दिनों में 690 वाहनों का चालान किया गया है। पेट्रोल पंप कर्मियों को हिदायत दी गई है कि बिना हेलमेट पेट्रोल न दिया जाए। कहा कि अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक भी किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। बिना हेलमेट के फ्यूल न देने का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि उनको जागरूक करना है।

टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में अधिकारियों संग छात्राओं का हुआ संवाद

जन एक्सप्रेस । अलीगढ़

विकसित भारत 2047 एवं उत्तर प्रदेश के विगत 8 वर्ष विषय पर मंगलवार को टीकाराम कन्या इंटर कालेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ इसमें शासन स्तर से आए वरिष्ठ अधिकारियों एन.सी. उपाध्याय, के.डी. वर्मा एवं के.डी. दीक्षित ने छात्राओं से संवाद स्थापित किया। विकसित भारत अभियान के अंतर्गत सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता एन.सी. उपाध्याय ने टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को विकसित भारत के 12 प्रमुख पैरामीटरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर को बढ़ाने, औसत आयु को 70 से 85 वर्ष तक ले जाने, क्लीन

एनजी को प्रोत्साहन देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सुलभ बनाने पर केंद्रित है।सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक के0डी0 दीक्षित ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार एवं जीडीपी वृद्धि से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम बताया। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए आप सभी द्वारा दिए गए सुझाव महत्वपूर्ण हैं।सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक के0डी0 वर्मा ने कहा कि भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश में 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण में बसती है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए 2047 तक 60 प्रतिशत शहरीकरण का लक्ष्य के साथ ही प्रत्येक जिले की एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी एवं ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने पर्यावरणीय संतुलन पर बल देते हुए बताया कि वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है।यदि हमारा तापमान 1 डिग्री सेटीग्रेड बढ़ता है तो उससे 1-1.5 प्रतिशत जीडीपी कम होती है।सभी अधिकारियों ने छात्राओं से शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सुधार, भविष्य की जरूरतों और विकसित भारत के विजन में उनकी सहभागिता को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। छात्राओं ने कहा कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक लैब की सुविधा बढ़ाई जाए। शिक्षकों को नई तकनीक का प्रशिक्षण मिले और पाठ्यक्रम में कौशल शिक्षा, करियर काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं शामिल हों।उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, छात्रवृत्ति, निशुल्क मार्गदर्शन, स्वच्छ एवं सुरक्षित

वातावरण और खेलकूद की सुविधाओं पर भी जोर दिया। छात्राओं ने सुझाव दिया कि एआई, रोबोटिक्स व कोडिंग जैसी नई तकनीकें पढ़ाई में शामिल हों और अभिभावकों व समाज की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा को और मजबूत बनाया जाए। छात्राओं ने विद्यालयों में बेहतर अधोसंरचना, स्मार्ट कक्षाओं का विस्तार, तकनीकी शिक्षा के अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन और कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी बातों पर भी अपने विचार रखे। सभी अधिकारियों ने कहा कि छात्राओं के सुझाव विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे निरंतर शिक्षा, नवाचार और सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें।

लूट की झूठी सूचना देने पर एजेंट पर दर्ज हुआ मुकदमा

जन एक्सप्रेस । उरई

कोतवाली क्षेत्र में पहल फाइनेंस प्राइवेट कंपनी में कलेक्शन एजेंट द्वारा दी गई झूठी लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पृछताछ के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई और पुलिस ने झूठी सूचना देने पर मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी। कुर्बंद थाना क्षेत्र के ग्राम खरका निवासी सौरभ यादव पुत्र सूरज यादव पहल फाइनेंस प्राइवेट कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता है। बताया गया कि मंगलवार की रात 9 बजे के करीब उसने पुलिस को सूचना दी कि वह किस्त के कलेक्शन का करीब एक लाख रुपये लेकर उरई आ रहा था। इस

राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन के सम्बन्ध में की गई चर्चा



जन एक्सप्रेस । महोबा

जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की मासिक बैठक, सम्भव अभियान की समीक्षा तथा राष्ट्रीय पोषण माह 12 सितम्बर से 11 अक्टूबर 2025 के सफल आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी है। बैठक में अनुपूरक पुष्टहार वितरण, हॉटकुव्ड मील योजना, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना

योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, पोषण ट्रेकर एप संचालन आदि विभागीय बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा तथा जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये है। साथ ही एफ0आरएस0 की फीडिंग, सैम-मैम बच्चों की पोषण श्रेणी में सुधार, गंभीर बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती कराना, सम्पन्न पंजीकृत लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टहार से आच्छादित कराना आदि विषयों पर

आवश्यकद् निर्देश निर्गत किए गये है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार, उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिला विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी चंद्र किशोर वर्मा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व समस्त सी0डी0पी0ओ0 व मुख्य सेविकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

अधेड़ महिला ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या

जन एक्सप्रेस/जालौन। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम एदलपुर में अधेड़ महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। जिससे उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम एदलपुर निवासी सुनीता देवी 55 वर्ष पत्नी शिवकुमार ने बुधवार को किन्हीं कारणों के चलते गांव में स्थित कुएं में छलांग लगा दी। घटना से गांव में अफरातफरी मच गई और परिजनों के अलावा गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। इस दौरान मौजूद लोगों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि महिला ने आए-दिन के गृह कलह से तंग आकर यह कदम उठया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।

वृहद मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता गोष्ठी एवं उपचार शिविर का एमएलसी ने कराया शुभारंभ

जन एक्सप्रेस । महोबा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आशाराम तथा नोडल अधिकारी डॉ वी. के.चौहान के निर्देशन में बुधवार विश्व आत्महत्या रोक थाम दिवस वृहद मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता गोष्ठी एवं उपचार शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह सेनार विधान परिषद सदस्य द्वारा फीता काटकर किया गया। स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित चिकित्सा अधीक्षक, डॉ पी0 के0 सिंह राजपूत, डॉ विनय कुमार, डॉ रोहित, डॉ आनंद तथा डॉ प्रेम दास मनोचिकित्सकी सामाजिक कार्यकर्ता आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग बारे में विस्तार से बताया गया जैसे याददाश्त की कमी, दिनचर्या को भूल जाना, याददाश्त जाना, भाषा का इस्तेमाल करने में दिक्कत, व्यक्ति में परिवर्तन, भटकाव, विषटनकारी या अनुचित व्यवहार, नकारात्मक विचार आना, किन्दगी में निराशा आना, अनिद्रा,



अवसाद, बेहोशी के दौरें आना, चक्कर आना, बुद्धि का कम विकास होना,भेद भाव, पूर्व जन्मो का अभिभाषा, सिर में दर्द, माइग्रेन, चिंता, घबराहट, झ़ाड,फूक, ऊपरी शक्ति का प्रभाव, तनाव प्रबंधन, सुसाइड प्रिवेंशन, शराब गाजा, अफीम, ड्रग्स, तथा आत्म हत्या के प्रमुख कारण मानसिक अस्वादा, नशा एवं ड्रग्स की लत, रोजगार तथा करियर में असफल होना, शारीरिक एवं मानसिक शोषण, प्यार में धोखा या ब्रेकअप, गंभीर बीमारी, संबंध विच्छेद एवं तलाक होना, आत्म हत्या

करने वाले लक्षण, अपने आप में खोए रहना, नकारात्मक सोचना, झूट बोलना, बार -बार मरने की बात करना, निराश वादी बात करना, खुद को चोट पहुंचाने तथा आत्महत्या की कोशिश करना छ कैसे मदद करे उसे कहीं अकेला न छोड़ें, बात करे अपना पन जताए, उसके साथ कोई फ़िएटिविटी करे, सकारात्मक विचारों का आदान-प्रदान करे, टेली मानस हेल्प लाइन न0 14416 पर बात करे, मानसिक स्वास्थ्य विभाग में संपर्क कर विशेषज्ञ से राय ले। योगा, मेडिटेशन, शारीरिक एक्सरसाइज,

टेली मानस हेल्प लाइन नंबर 1 8 0 0 8 9 1 4 4 1 6 , 18005990019 आदि पर बात करें आदि के विषय में बताया गया साथ ही बिना किसी झिझक के टीम के सामने आकर निराश कराने और समाज में व्याप्त भ्रांति को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। क्षेत्र से आये उपस्थित जन समूह एवं आशा, ए.एन.एम.स्टाफ, नर्स, अन्य कर्मचारियों को पम्पलेट वितरित किया गया।

शिविर में चिन्हित किये गये 35 मानसिक विकारों की पीढ़ित मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण कर दवा वितरित किया गया तथा मानसिक दिव्यांग प्रमाणपत्र भी जारी किए गए और कैप में 310 मरीज देखे गए छ इन्के उपरत परमर्श जिला अस्पताल के कमरा नंबर 4 में ओ.पी.डी. दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को समय 8 बजे प्रातः से 2 बजे अपराह्न तक सम्पर्क करने को बताया गया। चिन्हित किये गये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को नियमित आने की सलाह दी गई।

यूपीकेएल सीजन 2 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया समर्थन और आशीर्वाद

जन एक्सप्रेस । आगरा

उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (यूपीकेएल) के दूसरे सीजन के प्रति उत्सुकता बढ़ती जा रही है जो 25 दिसंबर, 2025 को शुरू होने वाला है। इस संबंध में एएसए अपलिफ्ट कबड्डी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक संभव जैन ने लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री ने यूपीकेएल के आगामी सीजन के लिए अपना हार्दिक समर्थन व्यक्त कर आशीर्वाद दिया और राज्य में युवा सशक्तिकरण और खेल को बढ़ावा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस चर्चा में कबड्डी ही नहीं बल्कि बल्कि इससे आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे खेल परिवेश पर भी बातचीत हुई। माननीय मंत्री ने युवाओं की भागीदारी, सामुदायिक विकास

और राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए खेलों को एक निर्णायक और महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करने के अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। दोनों लीडर्स ने ऐसे सम्मिलित मंच बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान कर, पोषित कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की राह प्रदान करें। बैठक में कुणाल शर्मा, रचित शर्मा और श्रीमती वेदिका त्रिवेदी भी उपस्थित थीं, जो यूपीकेएल के कार्यान्वयन और रणनीतिक विकास के प्रमुख हैं। एमजे अपलिफ्ट कबड्डी और यूपीकेएल जमीनी स्तर से लेकर पेशेवर स्तर तक की पाइप लाइन बनाने के अपने मिशन में अडिग हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य के हर कोने के प्रतिभाशाली एथलीटों के पास पेशेवर स्तर तक पहुंचने, विकसित होने और प्रसिद्ध होने के अवसर हैं।

हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के द्वारा एनीमिया को लेकर छात्राओं को किया गया जागरूक

जन एक्सप्रेस । महोबा

महिला कल्याण विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में वूमेन योजना के अंतर्गत दिनांक 2.9.2025 से 12.9.2025 तक 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय महोबा में महिला एवं किशोरी स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को एनीमिया के कारण लक्षण बचाव एवं उपचार संबंधी जानकारी प्रदान करना था जिला मिशन कोऑर्डिनेटर श्रीमती



प्रिया गुप्ता ने एनीमिया को साइलेंट किलर बताते हुए बताया कि यह रोग मुख्यतः आयरन की कमी से होता है और बच्चों किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं में अधिक पाया जाता है उन्होंने एनीमिया के बचाव हेतु संतुलित आहार हरी पत्तेदार सब्जियां

अंकुरित अनाज गुड डाले एवं आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन पर विशेष बल दिया। साथी आयरन फोलिक एसिड की गोलीयां नियमित रूप से लेने और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच करवाने की भी सलाह दी गई

नेपाल : नवलपरासी जेल से सैकड़ों कैदी हुए फरार, वीडियो वायरल

- प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवास व सरकारी भवनों को निशाना बना किया आग के हवाले
 - आगजनी-फायरिंग के बीच कैदियों ने जेल का ताला खुलवाकर सामूहिक रूप से फरार
- जन एक्सप्रेस।

महाराजगंज/नेपाल

नेपाल में हिंसक झड़प के बीच नवलपरासी जिला जेल में बंद करीब 500 कैदियों के फरार होने का वीडियो इंटरनेट के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक बुधवार को पड़ोसी मुल्क नेपाल के नवलपरासी जिला जेल में प्रदर्शनकारियों ने जिला जेल में तैनात सशस्त्र एवं नेपाल प्रहरी के जवानों को बंधक बना, उनके हथियार छीनकर हवाई फायरिंग करते हुए दहशत का माहौल बनाया। जिला कारागार में आगजनी और फायरिंग के बीच कैदियों ने जेल का ताला खुलवाकर सामूहिक रूप से फरार होने की वारदात को अंजाम दिया।



घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कैदी कफ्यू के बावजूद अपने-अपने सगे संबंधियों के साथ रवाना हो गए। जिससे सुरक्षाबलों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

घटना ने जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर सुरक्षाकर्मों कैदियों के कब्जे में रहे, वहीं दूसरी ओर समय रहते नियंत्रण न होने से सभी बंदी फरार हो गए। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घटना के बाद पुलिस और

सुरक्षा बलों की टीम फरार कैदियों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। हर आने-जाने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। नवलपरासी की इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।

इस बाबत नवलपरासी प्रमुख जिलाधिकारी हीरालाल रेग्मी ने बताया कि कई अपराधिक मामलों में करीब 500 कैदी जिला जेल में बंद थे जो सभी कैदी सभी कैदी फरार हो गए हैं। नवलपरासी जिले में कफ्यू जारी है, हालात पर नियंत्रण करने के लिए सेना के जवान सड़कों पर पहरा



दे रहे हैं। नेताओं के आवास व सरकारी भवनों को प्रदर्शनकारियों ने बनाया निशाना- नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में भड़की हिंसा की आंच में प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवास व सरकारी भवनों को निशाना बनाकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। जिसमें नवलपरासी प्रतिनिधि निर्वाचन सभा सदस्य क्षेत्र 1 सांसद विनोद चौधरी के सचिवालय, लुबिनी प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री देवकरण कलवार, पूर्व मंत्री हृदयेश त्रिपाठी, संविधान सभा सदस्य विक्रम

खनाल, लुबिनी सभासद विश्व प्रेमपाठक, एमाले जिलाध्यक्ष विपिन अधिकारी, एमाले जिला सचिव धिरज शर्मा, प्रतापपुर गांव पालिका अध्यक्ष उमेश यादव, पाल्हीनंदन गांव पालिका अध्यक्ष दीपक गुप्ता, उपाध्यक्ष फातिमा, एमाले लुबिनी प्रदेश के नेता धान प्रसाद गहौर, सुनवल नगर पालिका अध्यक्ष रेशम शर्मा तथा माओवादी कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय, वर्दघाट में राष्ट्रीय आवास में उपद्रवियों द्वारा जमकर तोड़फोड़ कर आग लगा दिया और तमाम वाहन जलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है।

नेपाल में बवाल: हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई गई गश्त

जन एक्सप्रेस। महाराजगंज

भारत से सटे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों और अस्थिर हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा व पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने सीमा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त और सतर्क निगरानी बनाए रखने के लिए संबंधित को निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने ऑनलाइन बैठक कर एसडीएम निचलौल और एसडीएम नौतनवा को आदेश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सीओ के साथ लगातार भ्रमणशील रहें और किसी

भी परिस्थिति में शांति व्यवस्था भंग न होने पाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल से भारत लौट रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जाए।

इसी के साथ जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना संयुक्त रूप ने सोनौली बार्डर पहुंचे हालात का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने सीमा पर जाकर व्यवस्थाओं का गहन मुआयना किया तथा एसएसबी और अन्य सुरक्षा बलों के साथ बैठक कर मौजूदा हालात की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में गश्त और सर्विलांस की और तेज करने का आदेश दिया, वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने अधीनस्थों को

सतर्क रहते हुए किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार रहने का निर्देश दिया।

वही सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि नेपाल में हो रहे प्रदर्शनों का असर भारतीय सीमा क्षेत्र की शांति पर किसी भी कीमत पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बार्डर निरीक्षण के दौरान एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद, तहसीलदार नौतनवा कर्ण सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे में यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन नेपाल की परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है।

नेपाल में हालात बिगड़े: भारतीय बाजार में पसरा सन्नाटा, व्यापारियों की चिंता बढ़ी

जन एक्सप्रेस। दूरीबारी/महाराजगंज

नेपाल में जारी प्रदर्शन और बवाल का असर सरहद से सटे भारतीय कस्बा दूरीबारी के बाजारों में साफ दिख रहा है। सामान्य दिनों में नेपाली ग्राहकों से गुलजार रहने वाला यह बाजार इन दिनों सन्नाटे में डूब गया। ग्राहकों के आवागमन ना होने से अधिकांश दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान तक बंद कर दिए हैं। कपड़ा व्यापारी बलराम गुप्ता ने बताया कि दूरीबारी बाजार का बड़ा हिस्सा नेपाली ग्राहकों पर ही टिका हुआ है।



जायसवाल का कहना है कि सामान्य दिनों में उनकी दुकान ग्राहकों से खचाखच भरी रहती थी। लेकिन बीते सोमवार से नेपाल में बिगड़े हालात ने सीमावर्ती इलाके के कारोबार को पूरी तरह चरमरा दिया है। मिश्रान भंडार चलाने वाले चन्ने चाय वाले ने बताया कि नेपाली ग्राहकों की

अनुपस्थिति से उनकी दुकान में अब मुश्किल से कोई ग्राहक पहुंच रहा है। इस बाबत व्यापार मंडल अध्यक्ष भवन प्रसाद गुप्त का कहना है कि कस्बे का पूरा बाजार नेपाली ग्राहकों के भरोसे है। यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो यहां के व्यापार की रीढ़ टूट सकती है।

किशोरी को बिहार ले जाकर यौन शोषण करने का आरोप

जन एक्सप्रेस। देवरिया

बघौचघाट थाना क्षेत्र के 16 वर्षीय किशोरी को बिहार ले जाकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की दिव्यांग मां ने पुलिस को तहरीर देर कारवाई की मांग की। जब थाने से न्याय नहीं मिला तो उसने मंगलवार को एसपी विक्रांत वीर से शिकायत की। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि बेटी कोगांव की एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर एक सितंबर को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली गई। उसने इसकी शिकायत तीन सितंबर को प्रधान से की थी। जब आरोपियों पर दबाव बढ़ा तो वह छह सितंबर की दोपहर में बेटी को लेकर बिहार चले गए। वहां उसे एक कमरे में ले जाकर आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। दिव्यांग मां ने आरोप लगाया है कि उसने जब इसकी शिकायत थाने में की तो कोई सुनवाई नहीं हुई।

नेपाल में दंगा-प्रदर्शन के बाद, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जन एक्सप्रेस। दूरीबारी/महाराजगंज

भारत से सटे नेपाल राष्ट्र में दंगा-प्रदर्शन और हालात पर काबू पाने के लिए नवलपरासी जिला सहित कई शहरों में कफ्यू लग गया है। ऐसे में भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बार्डर सीमा से सटे दूरीबारी कोतवाली क्षेत्र से लेकर लक्ष्मीपुर खुर्द चौकी तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। एहतियातन तीन थानों सिंदुरिया, कोठीभार सहित दूरीबारी की अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी सीमा पर लगा दी गई है।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में बिगड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीमा से सटे गांवों में चोर रास्तों और पगडंडियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी असांभाजिक तत्व की घुसपैठ या अवैध गतिविधि को रोका जा सके। बार्डर पर तैनात एसएसबी व पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा



क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है। आम जनता से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें।

नेपाल में प्रदर्शनकारियों की हिंसक गतिविधियों और कफ्यू के चलते वहां से आना नागरिकों का भारत आना-जाना लगभग ठप हो गया है। इसका असर सीमाई बाजारों पर भी

साफ दिखाई दे रहा है। सीमा चौकियों पर हर वाहन और राहगीर की गहन जांच की जा रही है। वही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स तैयार है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी साफ किया है कि भारतीय

सीमा में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस बाबत सीओ शिव प्रताप सिंह ने बताया कि नेपाल में तनाव को लेकर तीन थानों की अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है, बार्डर क्षेत्र के हर एक गतिविधियों पर पैनी नजर है।

भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ में हुई नई नियुक्ति राकेश गुप्ता बने संयोजक, मणिकांत द्विवेदी सह संयोजक हुए मनोनीत

जन एक्सप्रेस। महाराजगंज

भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए व्यापारिक प्रकोष्ठ में नई नियुक्तियों की हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पांडेय उर्फ संजय पांडेय ने जन एक्सप्रेस को बताया कि राकेश कुमार गुप्ता को व्यापारिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक तथा मणिकांत द्विवेदी को सह संयोजक मनोनीत किया गया है।

जिला अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी समाज भाजपा का सशक्त आधार है। सरकार की योजनाओं का लाभ व्यापारी वर्ग तक पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान हो और उन्हें समर्थन से जोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य से यह प्रकोष्ठ सक्रिय है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई जिम्मेदारी सँभालने वाले पदाधिकारी पूरी निष्ठा



और समर्पण के साथ पार्टी और

समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

नई जिम्मेदारी मिलने पर संयोजक राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने जिस भरोसे के साथ उन्हें यह दायित्व सौंपा है, उसे वे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को सरकार और संगठन तक पहुंचाना तथा उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ना है। मैं जिले के प्रत्येक व्यापारी की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करूंगा।

इस दौरान जिला प्रभारी रामजीवावन मौर्य, पिछड़ा आयोग सदस्य जनार्दन गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष परदेशी रविदास, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, संतोष सिंह, नबजू यादव, राम हरख गुप्ता, मधु पांडेय, संतोष जायसवाल और गोलू सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

सीएम योगी ने की गोसेवा, भवानी-भोलू को दुलारा

जन एक्सप्रेस। गोरखपुर

मंदिर की गोशाला में एक मोर भी विचरण करता है। उसका नाम पुंज रखा गया है। विगत कई माह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोशाला में होते हैं तो पुंज उनके पास आ जाता है। मुख्यमंत्री उसे भी खूब स्नेह और भोजन देते हैं। बुधवार को भी उन्होंने पुंज को दुलारा और अपने हाथों से उसे गुड़ खिलाया। गोश्लपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशु-पक्षी प्रेम जगजाहिर है। इसका एक नजारा बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में एक बार दिखा। प्रातःकाल मंदिर परिसर भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोशाला में गोसेवा की और मोर को भी गुड़ खिलाया। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान गोसेवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। इसी क्रम में बुधवार सुबह भी उन्होंने मंदिर की गोशाला में समय बिताया और गोसेवा की।

सीएम डैशबोर्ड: महाराजगंज दूसरे स्थान पर

■ जिलाधिकारी के कड़े रुख का दिखा असर, विकास योजनाओं में रहा अवल

जन एक्सप्रेस। महाराजगंज



जनपद महाराजगंज ने एक बार फिर विकास का परचम लहराते हुए प्रदेश स्तर पर सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अगस्त माह के लिए जारी रैंकिंग में महाराजगंज ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि विकास श्रेणी में जनपद पहले पायदान पर रहा।

पिछले माह आठवें स्थान पर फिसलने के बाद इस बार की उपलब्धि प्रशासनिक सख्ती और योजनाओं की लगातार समीक्षा का परिणाम मानी जा रही है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने पिछली रैंकिंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए थे। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को फटकार लगाई

गई थी और विद्युत विभाग से तो स्पष्टीकरण तक तलब किया गया था। वही विकास श्रेणी की 78 योजनाओं में से 51 को ए ग्रेड, 5 को बी ग्रेड और 3 को सी ग्रेड प्राप्त हुआ। खास बात यह रही कि किसी भी योजना को डी ग्रेड नहीं मिला। वहीं, राजस्व श्रेणी की योजनाओं में 31 को ए ग्रेड, 8 को बी ग्रेड और 2 को सी व डी ग्रेड में रखा गया।

सामूहिक प्रयास का परिणाम

रैंकिंग सुधार पर जिलाधिकारी ने संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि अधिकारी और कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं को धरातल तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से

अपील की कि अच्छी योजनाओं का प्रदर्शन बरकरार रखा जाए और कमजोर योजनाओं में सुधार लाया जाए। मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन ने कहा कि विगत माह विकास श्रेणी में 22वें स्थान पर पहुंचने के बाद इस बार पहला स्थान मिलना निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाने वाला है। यह सब जिलाधिकारी के निर्देशन और टीमवर्क का परिणाम है।

क्या है सीएम डैशबोर्ड

सितंबर 2023 से शुरू सीएम डैशबोर्ड दो घटकों से राजस्व और विकास पर आधारित है। इसमें योजनाओं की प्रगति विभागवार प्रदर्शित की जाती है। पोर्टल पर वास्तविक समय में डेटा अपडेट होकर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। जिलाधिकारी द्वारा हर माह दो बार समीक्षा बैठक की जाती है, जबकि सीडीओ और एडीएम भी अलग-अलग विभागों का आकलन करते हैं।

डग्गामार वाहन चालकों की दबंगई, बस स्टेशन के सामने ही भर रहे सवारी

जन एक्सप्रेस। कुशीनगर

कसया के रोडवेज बस स्टेशन के पास सवारी भरने को लेकर डग्गामार वाहनों की मनमानी कम नहीं हो रही है। करीब एक माह पहले एक डग्गामार वाहन चालक को सवारी बैठने से मना करने पर नाराज चालक ने पड़ौना डिपो के एआरएम को कुचलने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की थी।



नहीं लग पा रहा है। रोडवेज बस स्टेशन से बुलाकर प्राइवेट बस चालक व परिचालकों की तरफ से अब फिर से सवारी बैठया जा रहा है। इसको लेकर डग्गामार वाहन और रोडवेज बस चालकों के बीच कई बार विवाद होना फिर से शुरू हो गया है। हालत यह है कि प्राइवेट बस

चालक रोडवेज बस स्टेशन के गेट तक पहुंच आते हैं। यहां सवारी यदि उन्हें नहीं मिली तो बस स्टेशन रोडवेज बस की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को उनके गंतव्य तक जल्दी पहुंचाने का झांसा देकर बुला लेते हैं। यात्री भी अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचने की लालच में उनके बहकावे आ जाते हैं।

यदि इस दौरान कोई परिवहन निगम का कर्मचारी या उस दौरान निगम और अनुबंधित बस चालक या उरिकाचलक उनका विरोध करते हैं तो उनके बीच विवाद शुरू हो जाता है। हालांकि की निगम इन पर शिकंजा कसने के लिए बस स्टेशन के पास सवारी नहीं भरने का सख्त निर्देश दिया है। फिर भी नियमों का दारकिनार करते हुए धड़ले से डग्गामार बस चालक सवारी भरते रहते हैं।

राजू खान के पार्टी में शामिल होने से मजबूत होगी कांग्रेस- केशवचंद

जन एक्सप्रेस। देवरिया

मझौली राज में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में तीन बार दूसरे स्थान पर रहने वाले फिरोज अहमद उर्फ राजू खान ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवचंद यादव की मौजूदगी में लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। सलेमुपर पार्टी कार्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में ककार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशवचंद यादव ने कहा कि राजू खान के कांग्रेस में शामिल होने से संगठन को मजबूती मिलेगी। जिला उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र पांडेय ने कहा कि कर्मठ व जुझारू कार्यकर्ताओं का सम्मान सिर्फ कांग्रेस में है।

बीपैक्स महासदस्यता अभियान 12 सितंबर से शुरू

■ कृषक-अकृषक दोनों बन सकेंगे सदस्य, जारी होगा 10 अंकों का यूनिक कोड

■ कृषक पंजिका धारकों को उर्वरक, ऋण आदि योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता

जन एक्सप्रेस। महाराजगंज

जनपद के सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के उद्देश्य से बीपैक्स महासदस्यता अभियान शुभारंभ 12 सितंबर से किया जाएगा। यह अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवधि में किसानों के साथ-साथ अकृषक लोग भी समिति के सदस्य बन सकेंगे। समिति की सदस्यता लेने के लिए विभाग ने आसान व्यवस्थाएँ की हैं। इच्छुक लोग ऑफलाइन फॉर्म



भरकर, ब्यूआर कोड स्कैन करके, वेबसाइट pacsmember.in पर जाकर या फिर टोल-फ्री नंबर 1800-21288-4444 पर कॉल करके सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सदस्यता के लिए 100 रुपये के न्यूनतम दो शेयर, 21 रुपये सदस्यता शुल्क और 5 रुपये कृषक पंजिका शुल्क जमा करना होगा। विभाग द्वारा प्रत्येक सदस्य को 'कृषक पंजिका' जारी की जाएगी, जिसमें नाम, पता और कृषि रकबे

का विवरण दर्ज रहेगा। पुराने सदस्यों से मात्र 5 रुपये शुल्क लेकर कृषक पंजिका उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग का कहना है कि कृषक पंजिका से किसानों के विभागीय योजनाओं जैसे उर्वरक, ऋण आदि में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक नए सदस्य को 10 अंकों का एक यूनिक कोड भी जारी किया जाएगा, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ देने में आसानी होगी। अभियान को सफल बनाने के

लिए कलेक्ट्रेट सभागाार में जनपद स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त एवं उपनिबंधक गोरखपुर मंडल ने की। इस अवसर पर सभी सचिव, जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक तथा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सहकारी विभाग का मानना है कि इस अभियान से न केवल समितियों का सशक्तिकरण होगा, बल्कि किसानों को योजनाओं का लाभ सहजता से मिल सकेगा।

